



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

जो लिखेगा, वही टिकेगा

@swatantraprabhatmedia

@swatantramedia

RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)

@SwatantraPrabhatonline

news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, रविवार, 14 अप्रैल 2025

वर्ष 14, अंक 05, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

पुलिस मैदानगढ़ी और पुलिस नेब सरायके संयुक्त प्रयास से 3200 कार्टर और 02 कारों की बरामदगी...04

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश- राष्ट्रपति गवर्नरों के बिल पर 3 महीने में फैसला लें, सुप्रीमकोर्ट से सलाह लें

स्वतंत्र प्रभात

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। अदालत ने अनुच्छेद 201 के तहत समय पर कार्रवाई पर जोर दिया और विधायी प्रक्रियाओं में देवजह देरी पर चेतावनी दी। यही नहीं न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को विवेक के आधार पर राज्यपाल द्वारा असंवैधानिक माने जाने के आधार पर विचार के लिए रखे गए विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 का सहारा लेने से अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयकों के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में पक्षपात या दुर्भावना की किसी भी आशंका को कम किया जा सकता है।

राज्य विधानसभाओं के विधेयकों पर राज्यपालों को कार्रवाई के लिए समयसीमा तय करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्देश दिया कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर, राज्यपालों से प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अगर इस अवधि से अधिक समय तक देरी होती है, तो उचित वजहों को दर्ज करना और संबंधित राज्य को सूचित करना आवश्यक होगा।" कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल के फैसले को शुक्रवार को सार्वजनिक किया। उसने तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की कार्रवाई को अवैध और उल्टापूर ठहराया है। जबकि वे विधेयक पहले ही राज्य

विधानसभा द्वारा पुनर्विचारित किए जा चुके थे।

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन उचित समय के भीतर नहीं करता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने में असमर्थ नहीं रहेगा।" जहां राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते, तो राज्य सरकार को ऐसे कार्य के विरुद्ध इस संवैधानिक माने जाने के आधार पर विचार के लिए रखे गए विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 का सहारा लेने से अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयकों के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में पक्षपात या दुर्भावना की किसी भी आशंका को कम किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी आयोग ने इस विषय की ओर संकेत किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संदर्भों के शीर्ष निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समयसीमा जोड़ने का सुझाव दिया था। सरकारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. एस. सरकारिया ने की थी, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्था की समीक्षा के लिए



गठित किया गया था। पुंछी आयोग भी केंद्र-राज्य संबंधों पर था और इसे 2007 में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एम. एम. पुंछी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

अनुच्छेद 201 के अंतर्गत शक्तियों की व्याख्या करते हुए, पीठ ने कहा कि "यद्यपि तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं - या तो स्वीकृति देना या अस्वीकृति करना। बेंच ने यह भी कहा कि "अनुच्छेद 201 की एक विशेषता, जिसने वर्षों से केंद्र-राज्य संबंधों में मतभेद उत्पन्न किए हैं, यह है कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति घोषित करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है।"

फैसले में कहा गया कि "हम यह समझते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संकेत किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संदर्भों के शीर्ष निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समयसीमा जोड़ने का सुझाव दिया था। सरकारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. एस. सरकारिया ने की थी, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्था की समीक्षा के लिए

"बिना किसी वैध कारण या आवश्यकता के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय में देरी करना संविधान के उद्देश्यों के विरुद्ध है।" कोर्ट ने कहा कि "यद्यपि तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं - या तो स्वीकृति देना या अस्वीकृति करना। बेंच ने यह भी कहा कि "अनुच्छेद 201 की एक विशेषता, जिसने वर्षों से केंद्र-राज्य संबंधों में मतभेद उत्पन्न किए हैं, यह है कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति घोषित करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है।"

फैसले में कहा गया कि "हम यह समझते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संकेत किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संदर्भों के शीर्ष निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समयसीमा जोड़ने का सुझाव दिया था। सरकारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. एस. सरकारिया ने की थी, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्था की समीक्षा के लिए

फैसले में कहा गया कि "हम यह समझते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संकेत किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संदर्भों के शीर्ष निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समयसीमा जोड़ने का सुझाव दिया था। सरकारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. एस. सरकारिया ने की थी, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्था की समीक्षा के लिए

आखिरकार घोटाले की जाँच में दोषी ग्राम प्रधान पर कब होगी कार्यवाही

● ग्राम विकास अधिकारी ने किया था 13 लाख का घोटाला 120 शौचालय का रुपया किया गया गमन

घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी हुआ था निलम्बित

ग्राम प्रधान को बचाने में लगे अधिकारी कही घूस की भेंट न चढ़ जाए घोटाले की जाँच

स्वतंत्र प्रभात

कौशाम्बी। जनपद में सिरधु तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कशिषा पश्चिम में 20/03/2025 को कृषि उपनिदेशक के द्वारा ग्राम पंचायत में 13 लाख रुपये के घोटाला के मामले में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी सतीश



चौधरी को सरकारी शौचालय के घोटाले में निलम्बित किया गया था लेकिन ग्राम प्रधान बच निकले जिसकी जाँच कृषि उपनिदेशक ने किया था जिसमें शौचालय घोटाले की सत्यता देखी तो घोटाला सही पाया गया जिसमें केवल दो लोगों को शौचालय निर्माण का रुपया मिला था बाकी फर्जी लिस्ट देकर अधिकारी को गुमराह करने में कई ग्रामीणों से पूछा तो सच सामने आ गया लोगों ने बताया की वह अपने रूपयों से निर्माण कार्य कराया है प्रधान के द्वारा कोई भी राशि नहीं मिली जिससे जांच ग्राम पंचायत में 13 लाख रुपये के घोटाला के मामले में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी सतीश

जिन शौचालय की ग्राम प्रधान ने लिस्ट दिया था सभी फर्जी मिले थे ग्राम प्रधान पर आरोप लगाने की बात कही जिससे जांच कर रहे अधिकारी ने कहा कि एक भी लाभार्थी का नाम शौचालय की दीवाल में लिखा नहीं है अधिकारियों को गुमराह करने के लिए इधर-मिला था बाकी फर्जी लिस्ट देकर अधिकारी को गुमराह करने में कई ग्रामीणों से पूछा तो सच सामने आ गया लोगों ने बताया की वह अपने रूपयों से निर्माण कार्य कराया है प्रधान के द्वारा कोई भी राशि नहीं मिली जिससे जांच ग्राम पंचायत में 13 लाख रुपये के घोटाला के मामले में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी सतीश

भ्रष्टाचार यदि नगर पालिका प्रशासन करता कार्यवाही तो रुक सकता था अवैध निर्माण

बगैर जमीन फ्री होल्ड कराये और विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर होता रहा अवैध निर्माण और नगर पालिका प्रशासन रहा मौन

स्वतंत्र प्रभात

लखीमपुर खीरी एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश अपने मातहत को दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मातहतों के द्वारा अपनी ही सरकार का दो मंजिल पर भी छत पड़ गई इन पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?वही बेहद करीबी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया की कार्यवाही हो कैसे क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने भी तो आशा पैथोलॉजी वाली इमारत को बगैर फ्री होल्ड कराये और विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इसके जिम्मेदारों में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मूकदर्शनक की भूमिका में सब कुछ होते देखते रहे।ऐसे में शासन के आदेशों का प्रभावी अनुपालन हो पाना मात्र सपना बनकर रह गया है। यदि समय रहते साहब लोगों ने लिया होता सज़ान तो शायद अवैध निर्माण को

रोका जा सकता था ऐसा कई प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का कथन है।लोगों की जुबानी पर गौर करें तो जब अवैध तरीके से बनवाई गईं दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है तो नई बस्ती में मंदिर के रास्ते में रखा खोखा जो देखते-देखते पक्के निर्माण में तब्दील हो गया और सचिन श्रीवास्तव का दो मंजिल पर भी छत पड़ गई इन पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?वही बेहद करीबी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया की कार्यवाही हो कैसे क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने भी तो आशा पैथोलॉजी वाली इमारत को बगैर फ्री होल्ड कराये और विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर अवैध निर्माण कराया है।नगर पालिका में सब कुछ होते देखते रहे।ऐसे में शासन के आदेशों का प्रभावी अनुपालन हो पाना मात्र सपना बनकर रह गया है। यदि समय रहते साहब लोगों ने लिया होता सज़ान तो शायद अवैध निर्माण को

के कोई नियम कानून न लागू होते हो शायद इसीलिए अवैध निर्माण कार्य पर कारवाही न की जा रही हो ऐसा लोगों का आरोप है। इसे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर की मजबूरी कहे या बेवसी जिसकी वजह से शहर की काफी कोमती और कई जमीनों पर साधन संपन्न व रसूखदारों द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कराकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली गईं और नगर पालिका प्रशासन नोटिस पर नोटिस देता रहा।नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन की इस बेवसी के चलते शहर की वेशकीमती जमीनों पर साधन संपन्न रसूखदारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली जो शासन के आदेशों की खुली अवमानना को दर्शाती है और प्रशासन इन सब के सामने करीब अवस्था में खड़ा इनके ऊपर कार्यवाही करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। जब नगर पालिका अध्यक्ष ही करेंगी अवैध निर्माण तो कौन कराएगा कानून का पालन मामला स्थानीय शहर लखीमपुर के

अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती का है जहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ते हुए नजूल जमीन का पट्टा निरस्त होने के बाद भी जमीन को फ्री होल्ड कराये बगैर और विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराये बिना अवैध तरीके से पक्का निर्माण करा डाला गया।इतना ही नहीं बगैर ध्वस्तीकरण आदेश व मलवा निस्तारण आदेश के पुरानी इमारत को ध्वस्त कराकर नवीन निर्माण शुरू कर दिया गया।क्या यह नियम कानून का उल्लंघन एवं शासनविरोधी का नाफरमानी नहीं है।अधिशासी अधिकारी मजबूरन अपनी अध्यक्ष पर कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं।ऐसे में कानून का पालन कैसे हो पाएगा अहम सवाल बना है। साथ ही साथ पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है लोगों को कहना है जब माली ही बाग को खाएगा तो फिर कौन उसे बचाएगा?

अवैध निर्माण पर रोक के बावजूद कराए गए अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर जनपद खीरी में स्थानीय शहर के मोहल्ला नई बस्ती जहां पर दबंगों द्वारा

श्रीवास्तव द्वारा अधिशासी अधिकारी के निर्माण रोके जाने के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा और मकान पर छत डलवा दी। जो शासन के आदेशों की अवमानना है लोगों का कहना है कि आखिर इस अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर?जब दुकानों का ध्वस्तीकरण हो सकता है तो इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो सकता? क्या नगर पालिका प्रशासन व तहसील प्रशासन इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कराएगा यह सही माना जाए जिम्मेदारों को पता नहीं था। हकीकत तो यह है की जिम्मेदार जानकर भी अंजान बने बैठे हैं। वहीं सचिन

इतिहास में पहली बार- सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों पर राज्यपाल की मान्य स्वीकृति घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 10 कानूनों को लागू किया



स्वतंत्र प्रभात

तमिलनाडु सरकार ने 10 अधिनियमों के संचालन को अधिसूचित किया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा मान्य स्वीकृति घोषित किया था, क्योंकि राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने में बहुत देरी की थी और राष्ट्रपति को असंवैधानिक संदर्भ दिया था।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना निर्णय अपलोड किए जाने के बाद अधिसूचना जारी की। भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि कोई राज्य सरकार राज्यपाल की स्वीकृति के बिना न्यायालय के आदेश के आधार पर कानून लागू कर रही है। "इतिहास रचा गया, क्योंकि ये भारत में किसी भी विधानमंडल के पहले अधिनियम हैं, जो राज्यपाल/राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बल पर प्रभावी हुए हैं।" सीनियर एडवोकेट और डीएमके राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने जग पर पोस्ट किया। कुछ कानून राज्यपाल की झगड़ मुछामंत्री को यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बना देते हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि राज्यपाल 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि राज्यपाल द्वारा पहली बार स्वीकृति न देने के बाद उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया।

इसलिए विधेयकों को 18 नवंबर, 2023 को स्वीकृत माना गया, जिस दिन उन्हें सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1239/2023 में

दिनांक 08.04.2025 के अपने आदेश में आदेश दिया कि उक्त विधेयक को सुरक्षित रखने की तिथि के बाद माननीय राष्ट्रपति की सभी कार्रवाई गैर-कानूनी है और उक्त विधेयक को स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि को माननीय राज्यपाल द्वारा स्वीकृत मान ली गईं मानी जाएगी - अधिसूचित अधिनियम हैं-

- तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020।
- Also Read - राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय- सुप्रीम कोर्ट
- तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020
- तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2022।
- तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022
- तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई (संशोधन) अधिनियम, 2022।
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022।
- तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022।
- तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023।
- तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023।

आपसी विवाद के बाद दंपति ट्रेन के सामने कूदे, पत्नी की मौत पति घायल!

जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के इंद्रानगर नई बस्ती निवासी पति पत्नी शनिवार के सुबह करीब दस बजे आपस में विवाद कर लिए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों घर के पीछे से गुजर रही मालगाड़ी के सामने कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किए। जिसमें पत्नी की मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी होते ही परिजनों ने एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां पर पति का प्राथमिक उपचार कर ट्रामा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया गया है। महिला की मौत हो गई। कजाकपुर वाराणसी निवासी शानू पाल (24), अपनी पत्नी संगीता (21) निवासी शैलमूर्ति मोहल्ला के साथ लव मैरिज शादी की थी।



राजगढ़ थाना क्षेत्र के इंद्रानगर नई बस्ती में जमीन लेकर घर बना लिया था। जो अपने भाई के साथ बवाल में बने घर में रहता था। शनिवार को करीब 10 बजे किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों जान देने के लिए तैयार थे। जॉर्ज में कमी ही पायी गयी।

दौड़कर कूद गए। जिससे संगीता (21) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लती शानू पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर एंबुलेंस से दोनों पति-पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ लाया गया। जहां पर पति का प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया। जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ब्रिगड शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि दोनों में विवाद के बाद ट्रेन के सामने कूदने की जानकारी मिली है। महिला की मौत होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पति को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर भेजा गया है।



अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर के निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के बाद भी एक बाबू की सह पर अवैध निर्माण होते दिखाई पड़ा लोगों ने उक्त बाबू का नाम उजागर करते हुए दो अवैध निर्माणों पर प्रकाश डाला।

सूत्रों की माने तो मोहल्ला नई बस्ती में मंदिर के सामने कल तक खोखा रखा था आज वह पक्के निर्माण में तब्दील हो चुका है। और नगर पालिका प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।यह कहना कहां तक सही माना जाए जिम्मेदारों को पता नहीं था। हकीकत तो यह है की जिम्मेदार जानकर भी अंजान बने बैठे हैं। वहीं सचिन

संक्षिप्त खबरें

भाजपा स्थापना दिवस की साप्ताहिक पखवाड़ा के अवसर पर मंडल सिंहपुर में किया गया स्वक्षता है सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम



विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर शहडोल जिले के मंडल सिंहपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुशवाहा जी के साथ पूरे भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसके उपलक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व में माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमति अमिता चपरा जी के निर्देशानुसार मण्डल सिंहपुर में मण्डल अंतर्गत मां कंकाली मंदिर माता प्रांगण में स्वक्षता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें मुख्य रूप मण्डल अध्यक्ष सिंहपुर राकेश कुशवाहा जी, मण्डल महामंत्री राकेश कोल जी, मण्डल उपाध्यक्ष भानु प्रताप नापित एडवोकेट, मंदिर समिति के कार्यकर्ता एवं मण्डल अंतर्गत स्थित समस्त कार्यकर्ता वंशुओं के द्वारा स्वक्षता कार्यक्रम किया गया।

आंबेडकर जयंती "मनाने को



लेकर हुई बैठक"

सिद्धार्थनगर। चैतिया में 14 अप्रैल को परमपूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ.भभीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह, झांकी एवं शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर शनिवार को भटपुरवा, चैतिया, संग्रामपुर, ठीकहा, बस्ता, दासिया नेवरी, नवतला, बड़हरा अंसिधवा, सुधौली, सुकरोली, तीवर, असोक्वा, उडवलिया आदि गांवों में बैठक की गई। इस अवसर पर हरिश्चंद्र,रामकुमार शिवचरण, सतराम प्रधान, उमेश, राहुल कुमार ,राम कुमार, अशोक कुमार गौतम, एडवोकेट राजेश कुमार, जवाहरलाल श्री राम, बबलू, विष्णु प्रसाद, सुधिराम, सुभाष चंद्र, किशन लाल, शंभु गौतम, वीरेंद्र कुमार, मोतीलाल, रामविलास, मनोज कुमार, सुग्रीव प्रसाद, गगन कुमार, श्याम सुंदर, रवि कुमार,चंद्रिका प्रसाद बागदु , गोपाल, बैजू, लखन आदि लोग उपस्थित रहे।

पुलिस ने चलाया नशे के अवैध कारोबार पर चाबुक

कोसीकला पुलिस ने अन्तर्राज्यीय शराब तस्कन किया गिरफ्तार

मथुरा। नशा का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ मथुरा पुलिस ने कार्यवाही की है। थाना कोसीकला पुलिस ने एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कन को अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का मस्ताना ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोसीकला अरविन्द कुमार निर्वाली ने बताया कि सन्तोष पुत्र नारायन सिंह निवासी भत्ता कालौनी कस्बा व थाना कोसीकला शातिर शराब तस्कन है। ये लोग कोसीकला में कच्ची शराब बनाने मछियां चलाते थे। पुलिस की सख्ती के बाद इन्होंने दूसरे राज्यों में शराब की तस्करी का धंधा कर लिया। सतोष के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनाज मण्डी से भातू कालौनी की तरफ जाने वाले अवैध रास्ते पर थाना कोसीकला मथुरा से अन्तर्राज्यीय शराब तस्कन सन्तोष निवासी भत्ता कालौनी कोसीकला को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस ने 45 पौन्डा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का मस्ताना ब्राण्ड बरामद की है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है। थाना कोसीकला पुलिस ने एक और अभियुक्त नेम सिंह पुत्र पूरन निवासी रुपनगर थाना कोसीकला को शराब तस्कन के आरोप में गिरफ्तार किया है। धानौता पेट्रोल पंप के पास बनी झोपडी के पास से नेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 44 पैकेट अवैध देशी शराब दोस्ताना ब्राण्ड उत्तर प्रदेश मार्का के बरामद हुए।

वहीं थाना शेरगढ पुलिस ने एक व्यक्ति को 80 पन्डा देशी हरियाणा मार्का शराब व करीब दो किलो यूरिया सहित गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना शेरगढ प्रदीप कुमार ने बताया कि दिवश देकर अभियुक्त को उडानी रोड पर बनी स्व. चेताराम मुकदम धर्मशाला थाना क्षेत्र शेरगढ जनपद मथुरा से अभियुक्त दीपक पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम राजगढी थाना कोसीकला जनपद मथुरा को 80 पन्डा देशी हरियाणा मार्का शराब व यूरिया 1 किलो 900 ग्राम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक

पुलिस मैदानगढ़ी और पुलिस नेब सरायके संयुक्त प्रयास से 3200 कार्टर और 02 कारों की बरामदगी

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। दक्षिण जिले के कर्मचारियों को विशेष रूप से अपराध पर अंकुश लगाने और दक्षिण जिले के अधिकार क्षेत्र में शराब तस्करो/जुआरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम सौंपा गया था। तदनुसार, बीट-स्टाफ ने स्थानीय मुखबिरों को संवेदनशील बनाकर और मानव खुफिया जानकारी एकत्र करके ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। चौतरफा अभियान के क्रम में, ऐसे हाताश अपराधियों को पकड़ने के लिए नियमित रूप से रणनीतिक स्थानों पर जाल बिछाए गए पीएस मैदानगढ़ी 11 अप्रैल की मध्य रात्रि में पीपी भाटी माईंस, पीएस मैदानगढ़ी की पुलिस टीम जिसमें एसआई सौरभ अरोड़ा, एचसी हरीश चंद्र, एचसी राकेश, एचसी अमित और कांस्टेबल जोगिंदर शामिल थे, इंस्पेक्टर अमित कुमार, एसएचओ/मैदानगढ़ी के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त के लिए तैनात किए गए थे। गश्त के दौरान करीब 01-30 बजे जब टीम बांस गांव इलाके के पास पहुंची तो देखा कि एक कार (टेक्सी नंबर) सदिग्ध हालत में मंदर टेरेसा रोड से आ रही थी। शक होने पर चालक को रकने का इशारा किया गया लेकिन पुलिस की मौजूदगी



को भांपकर वह मौके से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि, सतर्क कर्मचारियों ने कड़ी मशकत के बाद कार को सफलतापूर्वक रोक लिया और चालक को काबू कर लिया। चेकिंग के दौरान कार से कुल 24 कार्टन के लिए तैनात किए गए थे। गश्त के दौरान करीब 01-30 बजे जब टीम बांस गांव इलाके के पास पहुंची तो देखा कि एक कार (टेक्सी नंबर) सदिग्ध हालत में मंदर टेरेसा रोड से आ रही थी। शक होने पर चालक को रकने का इशारा किया गया लेकिन पुलिस की मौजूदगी

शुरू कर दी गई है। मध्य रात्रि में थाना नेब सराय की पुलिस टीम जिसमें एसआई विवेक, एसआई रोहिताश, एचसी राजपाल, एचसी मलकीत और कांस्टेबल सुनील शामिल थे, इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एसएचओ/नेब सराय के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त के लिए तैनात थे। गश्त के दौरान लगभग 02:45 बजे जब टीम एससीडी स्कूल के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक कार सदिग्ध हालत में खड़ी थी। कार की जांच करने पर उसमें से 2000 कार्टर

शराब के कुल 40 कार्टन बरामद किए गए। बाद में उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई। इस संबंध में थाना नेब सराय में एफआईआर संख्या 181/25, दिनांक 11.04.25 यू/एस 33 दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। प्रस्तावित के बादसचिन पुरज जयदेव निवासी गांव अनगपुर, थाना सूरज कुंड, जिला फरीदाबाद तथा विशाल पुत्र राम कुमार निवासी एल-1 संगम विहार, को गिरफ्तार कर लिया गया।

पंचायत चुनाव में दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मृत्युंजय नाथ का नामांकन दाखिल

● श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा जिला परिषद की सीट पर तीव्र प्रतियोगिता के तहत निर्दलीय और BJP प्रत्याशी के बीच तगड़ी लड़ाई।

स्वतंत्र प्रभात

असम सहित श्रीभूमि जिले में पंचायत चुनाव शुरू होने के कारण विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता अपने संभावित उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर मैदान में उतर गए हैं। दूसरी ओर दुल्लभछड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के मतदाताओं को डीलिटिमेंशन के बारे में गुस्सा व्यक्त करते देखा जा रहा है। डीलिटिमेंशन के बाद कई लोग शायद सोच रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यहां से भाजपा आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब दिख रहा है कि कोई भी किसी को खाली मैदान में गोल नहीं दे सकता। अब तक दो उम्मीदवारों के बीच कट्टर लड़ाई होने की बात सुनी जा रही है। अब देखने की बात है कि जनदेवता की लोकप्रियता को कौन हासिल करता है और वही विजयी होगा, वहीं जनता किस पर जिम्मेदारी सौंपती है। नामांकन दाखिल करने के बाद श्रीभूमि जिले के प्रसिद्ध वकील पंचायत चुनाव में दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार श्रीभूमि जिले के प्रसिद्ध वकील मृत्युंजय नाथ ने गत 11 अप्रैल (शुक्रवार) को रामकृष्णगर सम-जिला कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया और दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट पर झुंझक के उम्मीदवार के रूप में मैदान में प्रणव मुखर्जी ने भी गत 10 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस समय दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट

को लेकर पंचायत चुनाव में गर्मागर्म माहौल बना हुआ है। एक ओर भाजपा उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी हैं, दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार प्रसिद्ध वकील मृत्युंजय नाथ हैं। दूसरी ओर दुल्लभछड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के मतदाताओं को डीलिटिमेंशन के बारे में गुस्सा व्यक्त करते देखा जा रहा है। डीलिटिमेंशन के बाद कई लोग शायद सोच रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यहां से भाजपा आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब दिख रहा है कि कोई भी किसी को खाली मैदान में गोल नहीं दे सकता। अब तक दो उम्मीदवारों के बीच कट्टर लड़ाई होने की बात सुनी जा रही है। अब देखने की बात है कि जनदेवता की लोकप्रियता को कौन हासिल करता है और वही विजयी होगा, वहीं जनता किस पर जिम्मेदारी सौंपती है। नामांकन दाखिल करने के बाद श्रीभूमि जिले के प्रसिद्ध वकील पंचायत चुनाव में दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार श्रीभूमि जिले के प्रसिद्ध वकील मृत्युंजय नाथ ने गत 11 अप्रैल (शुक्रवार) को रामकृष्णगर सम-जिला कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया और दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट पर झुंझक के उम्मीदवार के रूप में मैदान में प्रणव मुखर्जी ने भी गत 10 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस समय दुल्लभछड़ा जिला परिषद सीट



के बाद मेरा पहला लक्ष्य होगा जिला पंचायत के तहत जितने भी कार्य हों, सभी कार्यों को जनता की राय के अनुसार वास्तविक रूप देना और पारदर्शिता के साथ काम करना। इसके अलावा, जनता के लिए निस्वार्थ सेवा कार्य करते रहना।

कुछ सालों से एनजीओ के माध्यम से जनकल्याण के लिए लोगों के साथ खड़ा हूं और भविष्य में सेवा का एकमात्र अवसर देने के लिए जनता से अपील करते हैं। साथ ही एनजीओ के माध्यम से जिस तरह काम किया है, सामान्य लोगों के बारे में सोचते हुए कि निरंतरता से लोगों की सेवा में लगाव विकासोन्मुख कार्य करना चाहता हूं। दूसरी ओर, दुल्लभछड़ा जिला पंचायत में चार ग्राम पंचायत हैं, जिनमें दरगाबंद, भेटारबंद, दुल्लभछड़ा, विद्यानगर शामिल हैं, प्रसिद्ध वकील मृत्युंजय नाथ कई दिनों से इस क्षेत्र के घर-घर जाकर सामान्य लोगों का हालचाल ले

रहे हैं और उनकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी मुझे सेवाओं के लिए अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, देखते हैं कि भगवान और जनता का आशीर्वाद हाथ में होता है, तो मैं निश्चित रूप से विजय होने की आशा व्यक्त किया। इस बीच, इस बार उम्मीदवारों के बीच काटे की टक्कर होगी ऐसा सुनने में आ रहा है मतदाताओं से। दूसरी ओर, बंगाली, हिंदी भाषी और मेडरेट मणिपुरी को भाजपा द्वारा उम्मीदवार के रूप में पार्टी से टिकट न देने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की गलियों में वे बातें सुनी जा रही हैं कि भाजपा की इस सोच को लेकर क्षेत्र के आम लोग नाराजगी जता रहे हैं, इस विषय पर मतदाता वर्ग में चर्चा भी जारी है। इस बार राजनीतिक हलकों के विचारधाराओं के परिणाम क्या होंगे और जनता किसे चुनकर जीत दिलाएगी, दुल्लभछड़ा जिला परिषद निर्दलीय या भाजपा उम्मीदवार, यही अब ध्यान का विषय बन गया है।

रहे हैं और उनकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी मुझे सेवाओं के लिए अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, देखते हैं कि भगवान और जनता का आशीर्वाद हाथ में होता है, तो मैं निश्चित रूप से विजय होने की आशा व्यक्त किया। इस बीच, इस बार उम्मीदवारों के बीच काटे की टक्कर होगी ऐसा सुनने में आ रहा है मतदाताओं से। दूसरी ओर, बंगाली, हिंदी भाषी और मेडरेट मणिपुरी को भाजपा द्वारा उम्मीदवार के रूप में पार्टी से टिकट न देने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की गलियों में वे बातें सुनी जा रही हैं कि भाजपा की इस सोच को लेकर क्षेत्र के आम लोग नाराजगी जता रहे हैं, इस विषय पर मतदाता वर्ग में चर्चा भी जारी है। इस बार राजनीतिक हलकों के विचारधाराओं के परिणाम क्या होंगे और जनता किसे चुनकर जीत दिलाएगी, दुल्लभछड़ा जिला परिषद निर्दलीय या भाजपा उम्मीदवार, यही अब ध्यान का विषय बन गया है।

मंडी में खुले में पड़ा किसानों का गोहूँ

● भाकियू सुनील ने की टीन टिन सेट खाली करने की मांग

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारियों ने मथुरा मंडी समिति में किसानों के अनाज रखने के लिए टिन सेट खाली करने की मांग के लिए मंडी सचिव पंकज शर्मा को ज्ञापन सौंपा। भाकियू सुनील के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी ने कहा कि मथुरा मंडी समिति में किसानों का अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। मंडी समिति में किसानों के अनाज रखने के लिए सिर्फ एक टिन सेट खाली है। बारिश पड़ने पर किसानों का अनाज पानी में बह जाता है। भारतीय किसान यूनियन सुनील के कार्यकर्ताओं ने पूर्व में टिन सेट खाली करने के लिए आंदोलन किया था। उसके बाद पांच नंबर प्लेट फॉर्म को



मंडी समिति में खुले में पड़ा किसान का गेहूँ। खाली किया गया। अब गेहूँ की फसल चल रही है किसान अपना गेहूँ लेकर जब मंडी समिति में आते हैं तो उनको अपना गेहूँ खुले आसमान के नीचे रखना पड़ता है। किसान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मंडी सचिव पंकज शर्मा ने आश्वासन दिया है कि पांच नंबर प्लेट फॉर्म खाली पड़ा है। किसानों के अनाज रखने लिए तीन नए प्लेट फार्म का प्रस्ताव पास हो चुका है। तीन

नए प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसी भी किसान को परेशानी न हो। किसानों के पीने के पानी के लिए मंडी समिति में तीन नई बोरिंग कराई गई है। एक आरओ को भी चालू कर दिया गया है और भी आरओ पीने के पानी के लिए मंडी समिति में लगाए जाएंगे। मंडी सचिव पंकज शर्मा के आश्वासन के बाद ही किसान नेता मंडी समिति कार्यालय से बहार प्लेट फार्म का प्रस्ताव पास हो चुका है। तीन

निजी स्कूलों को नहीं मिलेगी लूट की छूट

● जिलाधिकारी बोले स्कूल प्रबंधकों की शीघ्र बुलाएंगे बैठक

समस्याओं के समाधान को संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। छात्रों व अभिभावकों की समस्याओं व प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही लूट के संदर्भ में अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंप कर लूट मचाने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के विरुद्ध के साथ विस्तृत मांग की। अभिभावकों के कार्यालय की रूप से वार्ता करने के बाद जिला अधिकारी द्वारा तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर शीघ्र एक बैठक प्रबंधकों के साथ बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लूट किसी



निजी स्कूलों द्वारा की जा रही लूट के विरुद्ध अभिभावक संघ के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हुए। इस अवसर पर संघ के संस्थापक शशिभानू गर्ग, अध्यक्ष हेमेंद्र गर्ग, मंत्री जगत बहादुर अग्रवाल, परग गुप्ता, सचिन अशोष, आशीष वर्मा, सचिव चैधरी, आरोपा, श्रीकांत गुप्ता, राजीव बंसल, विजय चौधरी, सुधीर वर्मा, गगन बंसल आदि उपस्थित रहे। दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया।

राम भक्त हनुमान की भक्ती में सराबोर हुई कान्हा की नगरी

● हनुमान मंदिरों में हुआ अभिषेक, फूल बंगला एवं छप्पन गोग दर्शन

रामचरित मानस पाठ व भजन संध्या के कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। महानगर के हनुमान मंदिरों पर हनुमान जयन्ती के अवसर पर रामभक्त हनुमान का अभिषेक किया गया और छप्पन भोग के दर्शनों का आयोजन हुआ। सुबह से बोरिंग कराई गई है। एक आरओ को भी चालू कर दिया गया है और भी आरओ पीने के पानी के लिए मंडी समिति में लगाए जाएंगे। मंडी सचिव पंकज शर्मा के आश्वासन के बाद ही किसान नेता मंडी समिति कार्यालय से बहार प्लेट फार्म का प्रस्ताव पास हो चुका है। तीन

श्रीभूमि जिले के पंचायत चुनाव में दरगाबंद जीपी के पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कमलाकांत यादव

● निर्दली उम्मीदवार कमलाकांत यादव और भाजपाउम्मीदवार सुरेंद्र सिन्हा दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत के लिए काटे की टक्कर।

स्वतंत्र प्रभात

असम सहित श्रीभूमि जिले में पंचायत चुनाव शुरू होने के कारण निर्दलीय उम्मीदवार कमलाकांत यादव मैदान में उतर चुके हैं। रामकृष्णगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार के पंचायत चुनाव में दरगाबंद जीपी के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कमलाकांत यादव खड़े हैं। श्रीभूमि जिला तथा रामकृष्णगर समष्टि में गत 11 अप्रैल (शुक्रवार) को दरगाबंद जीपी के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य पद के निर्दलीय उम्मीदवार कमलाकांत यादव ने दुल्लभछड़ा विकास खंड कार्यालय जाकर बीडीओ के पास मनोनयन दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन दशकों से आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, बाद में पुच्छाछ के बादसचिन पुरज जयदेव निवासी प्रधान के रूप में कार्य किया है। बीच में एक साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में कविता की किताब लिखकर असम सरकार के तहत -भाषा गौरव आंचली- परियोजना के तहत कवि के रूप में असम के तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और सम्माननीय मंत्री (वर्तमान मुख्यमंत्री) हिमंत विश्व शर्मा महोदय की उपस्थिति में पचास हजार रुपये और सरकारी प्रशंसा पत्र दिया गया। यह दिन 2021 के 1 फरवरी का था, स्थान शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी में। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। शिक्षक के रूप में



उनका अच्छा नाम था। स्थानीय सीवीपी हाईस्कूल में लगभग ढाई दशक तक प्रतिष्ठा के साथ शिक्षकता की। वर्तमान में वे समाज सेवक में व्यस्त हैं। चंद्रगीति संस्था के साथ शिल्क रेंडियो केन्द्र में कई सालों तक बांसुरी बजाई। संगीत समारोह में लगभग बीस साल गायक और निर्देशक के रूप में कुशलता से कार्य किया। उनके जीवन में अब तक कोई काला दाग नहीं पड़ा। क्षेत्र के जनसामान्य उनका निस्वार्थ समर्थन करते हैं। आसन्न पंचायत चुनाव में उक्त जीपी के एपी सदस्य लोकप्रिय पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों में चर्चा है और विश्व हिंदू परिषद के दुल्लभछड़ा प्रखंड के सह-प्रधान के रूप में कार्य किया है। बीच में एक साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में कविता की किताब लिखकर असम सरकार के तहत -भाषा गौरव आंचली- परियोजना के तहत कवि के रूप में असम के तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और सम्माननीय मंत्री (वर्तमान मुख्यमंत्री) हिमंत विश्व शर्मा महोदय की उपस्थिति में पचास हजार रुपये और सरकारी प्रशंसा पत्र दिया गया। यह दिन 2021 के 1 फरवरी का था, स्थान शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी में। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। शिक्षक के रूप में

भेटारबन्द जीपी के 3 नंबर वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिमल नाथ (अपु) ने नामांकन दाखिल किया

● आशावादी हैं कि उन्हें बहुत सारे वोटों से जीत मिलेगी।

स्वतंत्र प्रभात

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा विकास खंड कार्यालय में हजारों गांवों के लोगों के साथ भेटारबन्द जीपी के 3 नंबर वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिमल नाथ (अपु) ने नामांकन दाखिल करने के दूसरे या अंतिम दिन भी प्रत्याशियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उम्मीदवारों के बीच में भीड़ देखकर ऐसा ही अनुभव हुआ पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों से लेकर जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी एक-एक करके अपना नामांकन जमा किया है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मिलकर नामांकन पत्र जमा किया और वे अपनी राय प्रस्तुत किया है। श्रीभूमि जिला के रामकृष्णगर क्षेत्र में गत 11 अप्रैल



(शुक्रवार) को 100 से अधिक लोग एकत्रित होकर भेटारबन्द जीपी के 3 नंबर वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिमल नाथ (अपु) का नामांकन दाखिल करने के दूसरे या अंतिम दिन भी प्रत्याशियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उम्मीदवारों के बीच में भीड़ देखकर ऐसा ही अनुभव हुआ पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों से लेकर जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी एक-एक करके अपना नामांकन जमा किया है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मिलकर नामांकन पत्र जमा किया और वे अपनी राय प्रस्तुत किया है। श्रीभूमि जिला के रामकृष्णगर क्षेत्र में गत 11 अप्रैल



घाटी वाले हनुमान मंदिर में हनुमानजी का पंचामृत अभिषेक करते मंदिर के महंत बलदेव प्रसाद आशिया

एवं चरण सेवक सोनू पंडित व मोनू पंडित ने किया। अभिषेक दर्शनों के समय मंदिर में काफी संख्या महिला पुरुष भक्त हनुमानजी और रामजी से संबंधित भजन गा रहे थे। भाक्तगौरों ने साथ में पूजा अर्चन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सायंकाल प्राचीन मन्दिर घाटी वाले बाबा गूजर घाटी चौक बाजार मथुरा पर श्री राम केशर, श्री हनुमन्त लाल जी एवं श्री श्रीनाथ जी के समक्ष विभिन्न सामग्री सहित भव्य विशाल छप्पन भोग ठक्कुरजी को अर्पण किये गये। भव्य फूल बंगला में विराजे ठक्कुरजी की

परिक्रमा मार्ग में अब अतिक्रमण किया तो लगेगा आर्थिक दंड

● अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च की वसूली करेगा नगर निगम

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। नगर निगम अतिक्रमण हटाना है और आदतन लोग अतिक्रमण करते रहते हैं। यह सिलसिला अब थमेगा। नगर निगम अब अतिक्रमण हटाने आने वाले खर्च की वसूली अतिक्रमण करने वालों से करेगा। इसके लिए अतिक्रमण करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन प्रतिदिन होता है। वृंदावन संख्या में श्रद्धालु परिक्राम करते हैं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग को लगातार अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीमों कार्यवाही करती हैं। दूसरी ओर श्रद्धालुओं के आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं इसका लाभ उठाने के लिए परिक्रमा मार्ग में



वृंदावन में परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने नगर निगम की जेसीबी। अतिक्रमण करने वाले लगातार कार्यवाही के बाद भी अपने अभियान को आगे बढ़ाते रहे हैं। श्रद्धालुओं को अवैध अतिक्रमण के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिक्रमा मार्ग में अवैध अतिक्रमण के कारण कई श्रद्धालुओं को चोट भी लगती रही है। जिला प्रशासन, नगर निगम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एवं पुलिस बल द्वारा वृंदावन परिक्रमा मार्ग से दो स्थानों पर



अवैध अतिक्रमण हटाना गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने परिक्रमा मार्ग पर निवासित लोगों से अपील की है कि जिन्होंने परिक्रमा मार्ग में अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वह परिक्रमा मार्ग अतिक्रमण हटा दें। विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने पर नियम अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अर्थ दंड भी लगाया जाएगा, जिसके लिए स्वयं अतिक्रमणकर्ता जिम्मेदार होगा।